

एक चीन नीति

चर्चा में क्यों?

- अपने चुनाव अभियान के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के नवनरिवाचति राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 'एक चीन नीति' पर सवाल खड़े किये।
- ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन के बुलावे को स्वीकार करके तथा टीवी और सोशल नेटवर्क साइट ट्विटर पर 'एक चीन नीति' पर सवाल खड़े करके ट्रंप ने संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच कूटनीतिक संबंधों का रुख बदल दिया।
- 'एक चीन नीति' एक नाजुक संतुलन बनाए रखने वाली नीति है जिसे चीन ने कई दशकों में कायम किया है और ट्रंप द्वारा इस पर सवाल खड़े करने से चीन द्वारा स्वाभाविक रूप से एक तीक्ष्ण प्रतिक्रिया की अपेक्षा की जा रही है जो अमेरिका का सबसे बड़ा देयता और व्यापारिक भागीदार है।
- डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर तीक्ष्ण प्रतिक्रिया देते हुए चीन के वदेश मंत्री ने इस बात की चेतावनी दी कि अमेरिका की एक चीन नीति में कोई भी फेरबदल वाशिंगटन और बीजिंग के बीच के संबंधों को नष्ट कर देगा।

क्या है एक चीन नीति?

- यह चीन के उस पक्ष का कूटनीतिक समर्थन है कि विश्व में सिर्फ एक चीन है और ताइवान चीन का ही एक हिस्सा है।
- एक नीति के तौर पर इसका अर्थ है कि 'पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना' (चीनी जन-गणराज्य या पी.आर.सी., जो चीन का मुख्य भू-भाग है) से कूटनीतिक संबंधों के इच्छुक देशों को 'रिपब्लिक ऑफ चाइना' (चीनी गणराज्य या आरओसी यानी ताइवान) से संबंध तोड़ने होंगे।
- इस नीति के तहत अधिकांश देशों के औपचारिक संबंध ताइवान के बजाय चीन के साथ हैं। ताइवान को चीन अपने से टूटकर अलग प्रदेश मानता है, जो एक दिन मुख्य चीन में मिला जाएगा।
- यद्यपि ताइवान की सरकार का यह मानना है कि यह एक स्वतंत्र देश है, जो औपचारिक रूप से 'रिपब्लिक ऑफ चाइना' कहा जाता है, लेकिन इस नीति (एक चीन नीति) के कारण ताइवान अंतरराष्ट्रीय समुदाय से पृथक् पड़ गया है।
- ज्ञातव्य है कि जनवरी 2017 में ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन (Tasiing-wen) ने अमेरिकी यात्रा संपन्न की थी तो चीन ने इस पर बहुत तीव्र वरिध प्रकट किया तथा अमेरिका से बदला लेने की चेतावनी तक दे डाली।

एक चीन नीति का उद्भव

- इस नीति की शुरुआत 1949 से होने लगी थी, जब चीनी गृहयुद्ध के पश्चात् हारी हुई सत्ताधारी राष्ट्रवादी पार्टी जिसे 'कुओमिन्तांग' भी कहा जाता है, ताइवान लौटी और च्यांग काई शेक के नेतृत्व में वही 'रिपब्लिक ऑफ चाइना' की स्थापना की गई। जबकि जीते हुए साम्यवादियों ने 'पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना' की घोषणा की। दोनों पक्षों ने यह दावा किया कि वे पूर्ण चीन का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- तब से चीन के सत्ताधारी कम्युनिस्ट दल ने यह धमकी दी है कि अगर ताइवान स्वयं को कभी भी औपचारिक रूप से स्वतंत्र घोषित करता है तो वह उस पर बल प्रयोग करेगा, लेकिन हालिया वर्षों में उसने इस द्वीप के साथ नरम कूटनीतिक तरीके को अपनाया है।
- शुरुआत में अमेरिका समेत कई देश साम्यवादी चीन के बजाय ताइवान को तरजीह देते रहे थे, लेकिन कूटनीतिक रुख तब बदलने लगा जब 1970 के दशक की शुरुआत में चीन और अमेरिका ने रश्ति बनाने की पारस्परिक आवश्यकताओं को समझा और उसके बाद अन्य देश बीजिंग के पक्ष में टाइपेई (ताइवान की राजधानी) से रश्ति तोड़ने लगे।
- हालाँकि अब भी कई देश ताइवान के साथ व्यापार कार्यालयों या सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा अनौपचारिक संबंध बनाए हुए हैं और अमेरिका ताइवान का सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा और व्यापार मतिर देश है।

कौन वजिता है और कौन पराजति है?

- बीजिंग अपने दावे को मजबूती से आगे बढ़ाने में सक्षम रहा है और इस नीति से उसको सबसे अधिक फायदा हुआ है, जिससे ताइवान कूटनीतिक रूप से कमजोर हो गया है।
- विश्व के अधिकतर देशों और यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी ताइवान को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।
- हालाँकि, ताइवान अपने पड़ोसियों के साथ काफी सजीव आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध बनाए हुए है और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने भावनात्मक रश्तों का लाभ उठाकर कई छूटें भी प्राप्त करता है। जहाँ तक अमेरिका का संबंध है, तो हालिया घटनाओं को या तो भारी भूल कहा जा रहा है या एक कुशल रणनीतिक चाल।
- भारी भूल इसलिए क्योंकि इससे अमेरिका और चीन के बीच दशकों से कायम कूटनीतिक संबंधों को हानि पहुँचा सकता है और कुशल रणनीतिक चाल इसलिए क्योंकि यह चीन को ताइवान और तबिबत के साथ उसकी अवच्छेद संप्रभुता को चुनौती देकर, पीछे धकेल सकता है।

एक चीन नीतिपर भारत का दृष्टिकोण

- चीन के कई पड़ोसियों की तरह भारत ने भी हालिया वर्षों में चीनी वदिश नीतिके अधिक स्वीकारात्मक और राष्ट्रवादी ब्रांड को ही अपनाया है ।
- इन द्विपक्षीय संबंधों में कई बार घर्षण उत्पन्न हुआ, जैसे-वविदलि सीमाओं पर चीन द्वारा भारत में घुसपैठ करना, पाकस्तान आधारलि आतंकवादियों पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा आरोपलि प्रतर्बिंधों को रोकने के चीन के प्रयासों के बाद और भारतीय प्रधानमंत्री एवं दलाई लामा की अरुणाचल प्रदेश की यात्रा, जसिके अधिकतर हसिसे को चीन के द्वारा 'दक्षणी तर्बिबत' कहा जाता है, आदि।
- हालिया वर्षों में भारत ने चीन के साथ अधिक व्यावहारकि रवैया प्रदर्शति कयि है और चीन को यह संकेत दयि है कयिदउसे एक चीन नीतिपर भारत की स्वीकार्यता चाहयि तो चीन को कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भारतीय संप्रभुता को स्वीकार करना होगा ।

वदिश मंत्री सुषमा स्वराज के शब्दों में, 'भारत के एक चीन नीतिपर सहमत होने के लयि चीन को भी 'एक भारत नीति' की पुनः पुष्टिकरनी होगी ।'

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/a-china-policy>

